

प्रेषक,

ओम प्रकाश,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक

प्रशिक्षण विभाग,

हल्द्वानी (नैनीताल)।

**प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग-2**

देहरादून, दिनांक : 10 मार्च, 2017

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26 जुलाई, 2016 एवं शासनादेश संख्या-1391/XXVII(1)/2016 दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक/अनुपूरक मांग के माध्यम से प्रशिक्षण विभाग के अनुदान संख्या-16 के अधीन वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में संलग्न परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित विवरणानुसार ₹4,47,16 हजार (रुपया चार करोड़ सैतालिसलाख सोलह हजार मात्र) {आयोजनागत पक्ष में ₹3,10,68 हजार/- एवं आयोजनेत्तर पक्ष में ₹1600+12048=₹1,36,48 हजार/-} की अधोल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वहन पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1- वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय किशतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि का कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।
- 2- अधिष्ठान संबंधी अन्य अवचनबद्ध मदों की आय-व्यय के अन्तर्गत स्वीकृत बजट प्राविधान की धनराशि भी संबंधित प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा आहरण-वितरण अधिकारियों को इस प्रतिबंध के साथ उपलब्ध करा दी जायेगी कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।
- 3- योजनागत पक्ष में चालू योजनाओं में आय-व्ययक के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा आहरण वितरण अधिकारियों को इस प्रतिबंध के साथ निर्गत कर दी जायेगी कि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किशतों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।
- 4- व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों हेतु पूरे वर्ष के सम्भावित व्यय की फेजिंग कर कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त करायेंगे तथा लक्ष्य के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण किया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा।
- 5- किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्थोरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

- 6- यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
  - 7- अनुदानों को विभागवार एवं विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महालेखाकार के कार्यालय में व्यय को सही लेखाशीर्षक/अनुदान के अन्तर्गत पुस्तकित करने में कठिनाई होती है और सुसंगत लेखाशीर्षक/अनुदान के अधीन त्रुटि रह जाने की सम्भावना बनी रहती है। इस हेतु आवश्यक है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियाँ शासनादेश संख्या बी-2-2337/97 दिनांक 21 नवम्बर, 1997 के प्रारूप में सही लेखाशीर्षक इंगित करते हुये ही निर्गत की जाय, जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाये।
  - 8- विभाग में स्वीकृतियों एवं उसके सापेक्ष व्यय का रजिस्टर रखा जाय एवं प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना शासनादेशों की प्रतियां सहित वित्त एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
  - 9- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल चालू स्वीकृति योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों के कार्यान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
  - 10- उपनल के कार्मिकों को मानदेय/वेतन का भुगतान मानक मद-16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान से किया जाता है। इस संबंध में निदेशक प्रशिक्षण को निर्देशित किया जाय कि इस मद में प्राविधानित/स्वीकृत धनराशि से उपनल के कार्मिकों का वेतन आहरित कर व्यय किया जायेगा। अन्य किसी प्रकार की देयता वेतन से इतर इस मद में व्यय हेतु उत्पन्न होती है तो शासन की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
  - 11- आयोजनागत पक्ष में स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
  - 12- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2230-श्रम तथा रोजगार के अधीन संलग्नक परिशिष्ट-"क" में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।
  - 13- जिन मदों में वित्तीय वर्ष 2016-17 में लेखानुदान के माध्यम से स्वीकृत बजट के सापेक्ष धनराशि निर्गत नहीं की गयी है, उन मदों में आवश्यकता के दृष्टिगत औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।
  - 14- फर्नीचर व उपकरणों आदि का क्रय पदधारकों हेतु नियमानुसार निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।
  - 15- उपकरणों/निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु मानकों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाए।
  - 16- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2017 तक उपयोग करना सुनिश्चित करें। मितव्ययता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. "आयोजनागत पक्ष/आयोजनेत्तर पक्ष" में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में आय-व्ययक के 'अनुदान संख्या 16' के "आयोजनेत्तर/आयोजनगत पक्ष" के क्रमशः 'संलग्न परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।
3. यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में [www.cts.uk.gov.in](http://www.cts.uk.gov.in) से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. S1703160114, S1703160116, तथा S1703160118 के अन्तर्गत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:

847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26 जुलाई, 2016 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं। उक्त शासनादेश में उल्लिखित बिन्दुओं/दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए तदनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्ध शा0 पत्र संख्या : 265(N/P)/XXVII(5)/2017 दिनांक : 07 मार्च, 2017 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या :- 56 (1)/XLI-1/17-40(प्रशि0)/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ऑबेरॉय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी हल्द्वानी(नैनीताल)।
7. मुख्य वित्त अधिकारी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजना, हल्द्वानी-नैनीताल।
8. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)

अनुसचिव।